उत्तर प्रदेश-जर्मनी गेटवे के जरिए 20 एमएसएमई और स्टार्टअप्स को यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी

❑ एमएसएमई, स्टार्टअप्स, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक अवसरों को बढ़ावा देगी यूपी-जर्मनी साझेदारी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक ठोस वैश्विक मंच पर उठाने की दिशा में मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया। इसके तहत राज्य सरकार ने एक संरचित 'इंडो-जर्मन गेटवे कार्यक्रम' को आगे बढ़ाया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 20 प्रमुख एमएसएमई (MSME) और स्टार्टअप्स को जर्मनी तथा व्यापक यूरोपीय बाजारों में प्रवेश के लिए तैयार किया जाएगा। यह पहल राज्य के निर्यात, औद्योगिक निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नई मजबूती प्रदान करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अधिक प्रतिस्पर्धी निवेश केंद्र के रूप में उभरेगा।

इस दिशा में जर्मन इंडियन बिजनेस एलायंस (GIBA) और इनोवेशन हब राजस्थान के प्रतिनिधियों वाला एक उच्चस्तरीय जर्मन प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य 23 जनवरी, 2026 को फ्रैंकफर्ट में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में इन्वेस्ट यूपी और GIBA के बीच आदान-प्रदान किए गए समझौता ज्ञापन (MoU) के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना था।

प्रतिनिधिमंडल ने फ्रैंकफर्ट समझौता (एमओयू) के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की और एमएसएमई, स्टार्टअप्स, नवाचार, विनिर्माण, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, नागरिक उड्डयन तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में इसके क्रियान्वयन की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान के मेयर डेविड रैंडेल, इनोवेशन हब राजस्थान के सीईओ स्टीफन डिट्रिच, GIBA के सीईओ विपिन रमन कनौजिया और GIBA के चेयरमैन वेंकटकुमार परिपसामी शामिल थे। इन्वेस्ट यूपी में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव, MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन, आलोक कुमार तथा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के. वी. पांडियन भी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय और जर्मन इंडियन बिजनेस एलायंस (GIBA) के बीच एमएसएमई की वैश्विक बाजार पहुंच और अंतरराष्ट्रीय विस्तार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इंडो-जर्मन गेटवे कार्यक्रम निर्यात के लिए तैयार और विकासोन्मुख उद्यमों को जर्मनी तथा यूरोप में एक मजबूत व्यावसायिक उपस्थिति स्थापित करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करेगा। इसके तहत प्रस्तावित इंडो-जर्मन MSME एवं एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थानीय इकाइयों को निवेश, तकनीकी सहयोग और जर्मनी में व्यावसायिक अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साझेदारी के तहत गाजियाबाद कॉमन फैसिलिटी सेंटर के आधुनिकीकरण में भी जर्मन प्रिसिजन इंजीनियरिंग और उन्नत विनिर्माण विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा।

संयुक्त कार्यशालाओं के माध्यम से यूरोपीय संघ के व्यापार नियमों, जर्मन अनुपालन मानकों, निर्यात दस्तावेजीकरण और स्थिरता से जुड़े मानकों पर क्षमता निर्माण किया जाएगा। यह पहल ओडीओपी, स्टार्टअप नीति-2022 और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस जैसी राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के अनुरूप होगी तथा प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने पर भी केंद्रित होगी। प्रमुख सचिव, एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन आलोक कुमार ने कहा कि वर्ष 2026 भारत-जर्मनी संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि यह दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत में 2,000 से अधिक जर्मन कंपनियां कार्यरत हैं, जो उत्तर प्रदेश के उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती हैं।

श्री कुमार ने कहा कि अब इस समझौते (एमओयू) को व्यावहारिक व्यावसायिक परिणामों में बदलना होगा। हमारा लक्ष्य चयनित एमएसएमई और स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए तैयार करना और दीर्घकालिक व्यावसायिक साझेदारियां विकसित करना है।